शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

शिक्षकों को पदोन्नति पदनाम देने के लिए सीएम को लिखा पत्र

40 हजार शिक्षकों के प्रमोशन के लिए मंत्री तुलसीराम सिलावट आगे आए

भोपाल। मौजूदा राज्य सरकार में सिंधिया कोटे के सबसे ताकतवर मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि पदोन्नति पदनाम लेना शिक्षकों का मौलिक अधिकार है। यह एक ऐसी मांग है जिस पर कोई वित्तीय भार भी नहीं आ रहा है। इस संदर्भ में सिलावट ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा है। उन्होंने मास्टरों को यह भी भरोसा दिया है कि वह स्वयं इस संबंध में मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल समग्र शिक्षक संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री सिलावट के आवास पर पहुंचा था। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा शिक्षकों को पदोन्नति का पदनाम देने के संबंध में 23 दिसंबर 2017 को अपने गृह क्षेत्र नसरुल्लागंज में की घोषणा की गई थी। दुर्भाग्य है की इस घोषणा के 2 साल बाद भी अभी तक फाइल पर कार्यवाही करने की बजाएं उसे बंद कर दिया है। एक प्रकार से यह फाइल अब मंत्रालय में दीमक की भेंट चढ़ रही है। मौके पर समग्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश दुबे ने पक्ष रखा की नई भर्ती की प्रक्रिया के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणा के अनुसार शिक्षकों के पद अपग्रेड होना चाहिए। क्योंकि इस मामले में सीहोर कलेक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है। मंत्री ने मौके पर ही सीएम को पत्र लिखा और शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वह स्वयं इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान से भेंट करेंगे।

बीआरसीसी का भारी भरकम वजन देख मुस्कुराए मंत्री

अपने आवास पर मुलाकात के दौरान मंत्री सिलावट उस समय हास परिहास के अंदाज में नजर आए जब उन्होंने इस प्रतिनिधिमंडल के साथ भारी भरकम वजन वाले बीआरसीसी रविंद्र जैन को देखा। मंत्री ने पूछा भी कि ज्यादा वजन के कारण काम करने में दिक्कत आती होगी। तब मौके पर इस संगठन के जिलाध्यक्ष भोपाल महावीर शर्मा ने बताया कि अगर इनके काम का आंकलन किया जाए तो यह मेहनत में सबसे अग्रणी दिखेंगे।

तब मंत्री ने भी कहा कि इनसे अन्य ऐसे लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए जो भारी वजन के कारण स्वयं को परेशान समझते हैं। प्रतिनिधिमंडल में भोपाल जिला इकाई के पदाधिकारी सुनील कुमार मालवीय, अनिल हाड़ा, तेजराम धरते, विजय भार्गव, कालूराम महावर, राहुल शुक्ला, खुर्शीद आलम, प्रेमनारायण रघुवंशी आदि शामिल थे।

कोरोना पॉजिटिव विद्यार्थी नहीं बैठ पाएगा बारहवीं की परीक्षा में

आगामी 9 जून से प्रारंभ होने जा रही बारहवीं की शेष परीक्षा

भोपाल। आगामी 9 जून से प्रारंभ होने जा रही बारहवीं की शेष परीक्षाओं में वह विद्यार्थी नहीं सम्मिलित हो पाएंगे जो या तो खुद कोरोना पॉजिटिव भी या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य इस बीमारी से ग्रसित हुआ है। ऐसे छात्र.छात्राओं की परीक्षा कराने के लिए शासन अलग से विचार करेगा। बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल ने व्यवस्थाओं से संबंधित समस्त कलेक्टरों को आदेश जारी किया। इसमें कहा गया है कि जो छात्र छात्रा अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा में नहीं बैठाया जाएगा। मंडल का कहना है कि इस प्रकार के विद्यार्थियों की परीक्षा कराने के लिए शासन अलग से विचार करेगा। शासन के संबंध में जो निर्देश होंगे उसी के अनुसार इन विद्यार्थियों की परीक्षाएं करवाई जाएगी। बोर्ड सचिव ने कहा है कि विद्यार्थी लॉक डॉन के कारण किसी भी जिले में हो। वह प्रवेश पत्र दिखाकर परीक्षा में बैठ सकता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने मूल जिले के परीक्षा केंद्र से दूसरे जिले में है और वह ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाया है। तो ऐसी स्थिति में वह जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन देकर परीक्षा में बैठ सकता है। मंडल सचिव ने बताया है कि सभी विद्यार्थियों के ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जा रहे हैं। 4 जून से विद्यार्थी मंडल की वेबसाइट से प्रवेश पत्र अपलोड कर सकते हैं। मंडल का कहना है कि बाहरी राज्यों के जो छात्र मध्यप्रदेश में अध्ययन कर रहे थे और वह आपदा के समय अपने घरों तक पहुंचे हैं। वह छात्र अपने राज्यों की सीमा से सटे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में परीक्षा में बैठ सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए विद्यार्थियों की शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं संपादित करवाएं। परीक्षाओं में नकल ना हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा।

इजरायलः स्कूलों में फैला कोरोना, सात हजार छात्र, टीचर क्वारेंटाइन

एजेंसी | येरुशलम

इजरायल दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जिसने कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया है, पर देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 116 नए मामले सामने आ गए हैं। यह एक महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 1 मई को 155 मामले आए थे। इजरायल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा संक्रमण स्कूलों के कारण फैला है। इसके चलते 40 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं 7000 टीचर और छात्रों को क्वारेंटाइन कर दिया गया है। ताजा मामला येरुशलम का जिम्नेशिया हाई स्कूल का है। जो हॉटस्पॉट में बदल गया है। यहां 130 छात्र और स्टाफ के लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्कूलों और दूसरे संस्थानों में महामारी फैलने से इजरायल में संक्रमण का दूसरा दौर शुरू होने की चिंता पैदा हो गई है। इजरायल में महामारी के शुरूआती दौर में ही लॉकडाउन लगा दिया गया था। अप्रैल के मध्य में अनलॉक शुरू किया गया, और स्कूलों, ऑफिसों, दुकानों, रेस्तरां और समुद्र तटों को भी खोल दिया गया। देश में संक्रमितों की कुल संख्या 17342 हैं, वहीं कोरोना से 290 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 हजार लोग ठीक भी हो चुके हैं।

एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग

टॉप 100 में भारत के आठ संस्थान आईआईटी इंदौर 55वें नंबर पर

हरिभूमि ब्यूरो ▶▶ नई दिल्ली

टाइम्स हायर एजुकेशन की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इस साल भी इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस (आईआईएससी) बेंगलुरु देश के अंदर टॉप पोजिशन में है। वहीं ग्लोबल रैंकिंग में इसको 36वां स्थान मिला है। इसके अलावा भारत के आठ आईआईटी भी टॉप 100 की लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। इंदौर आईआईटी को 55वीं रैंक मिली है। 2016 के बाद से ये अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है। टॉप 100 में भारत के आठ संस्थान है।

आईआईएससी बेंगलुरु नंबर में आगे अव्वल

आईआईटी रोपड़ पहली बार टॉप 50 में शामिल

आईआईटी रोपड़ ने अप्रत्याशित प्रदर्शन किया है और पहली बार रैंकिंग में जगह मिली है। आईआईटी रोपड़ ने टॉप 50 में जगह बनाई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल आईआईटी खड़गपुर ने 17 पायदान और आईआईटी दिल्ली ने 24 पायदान छलांग लगाई है।

चीन को 81 विवि के साथ टॉप ग्लोबल रैंक

चीन ने न सिर्फ टॉप ग्लोबल रैंक हासिल की है बल्कि 81 यूनिवर्सिटियों के साथ टेबल में टॉप भी किया है। सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व वाला देश जापान है जिसके 110 संस्थान हैं।

एनसीईआरटी की जगह प्राइवेट पब्लिसर्स की किताबें खरीदने का दबाव

मप्र पालक महासंघ ने निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में शुरू किया अभियान

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

केंद्र सरकार सहित प्रदेश सरकार द्वारा एनसीईआरटी की किताबों को लेकर स्पष्ट निर्देश जारी होने के बाद भी निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। कई निजी स्कूल अभी भी अभिभावकों को प्राइवेट पब्लिसर्स की बुक खरीदने का दवाब बना रहे हैं। ऐसे में अब मप्र पालक महासंघ ने एनसीईआरटी की किताबों को लेकर निजी स्कूलों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। महासंघ सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों से पालकों से एनसीईआरटी की किताबें ही खरीदने की अपील कर रहा है।

लगातार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं

मप्र पालक महासंघ के अध्यक्ष कमल विश्वकर्मा ने बताया कि केंद्र सहित प्रदेश सरकार द्वारा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक एनसीआरटी की किताबें अनिवार्य की गई हैं लेकिन लगातार अभिभावकों से जानकारी मिल रही है कि स्कूल एनसीआरटी की बजाय लगभग 10 गुना महंगी प्राइवेट पब्लिसर्स की किताबें खरीदने का दवाब बना रहे हैं। विश्कर्मा ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मामले की कई बार शिकायतें करने के बाद भी विभाग और सरकार द्वारा कोई ठोस कारवाई नहीं की जाती है। नतीजन प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हैं। जिसका खामियाजा अभिभावकों को भुगतना पड़ता है। अब महासंघ ने अभिभावकों से एनसीआरटी की ही किताबें खरीदने सहित ऐसे स्कूलों के खिलाफ खुलकर सामने आने की अपील की है, ताकि मनमानी पर रोक लगाई जा सके।

हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यावसायिक परीक्षा की शेष बची परीक्षाएं 9 जून से होगी

पन्ना/माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित हायर सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक परीक्षा 2020 की शेष बची परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया है। यह परीक्षाएं 09 जून 2020 से प्रारंभ होकर पूर्व निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होना है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र एवं अन्य गोपनीय सामग्री संबंधित थानों से निकालने हेतु अधिकारियों को कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा वर्ष 2020 के समय सारणी के अनुसार संबंधित थाना में प्रातः 7 बजे स्वयं उपस्थित होकर प्रश्न पत्र निकलवाने की कार्यवाही सम्पादित कराएंगे।

उन्होंने बताया कि कोतवाली पन्ना के लिए सुश्री दीपा चतुर्वेदी तहसीलदार पन्ना, पुलिस चैकी बराछ के लिए जमुना प्रसाद रावत राजस्व निरीक्षक तहसील पन्ना, पुलिस चैकी ककरहटी के लिए राम नरेश गौतम राजस्व निरीक्षक ककरहटी, पुलिस थाना देवेन्द्रनगर के लिए सुश्री दिव्या जैन प्र. तहसीलदार देवेन्द्रनगर, पुलिस थाना बृजपुर के लिए सुशील कुमार तोमर अधीक्षक भू-अभिलेख पन्ना, पुलिस थाना सलेहा के लिए कृष्ण कुमार दुबे राजस्व निरीक्षक गुनौर, पुलिस थाना गुनौर के लिए आकाश नीरज ना. तहसीलदार गुनौर, पुलिस चैकी महेबा के लिए भोला प्रसाद साकेत राजस्व निरीक्षक, पुलिस थाना अमानगंज के लिए रामलाल विश्वकर्मा प्र. तहसीलदार अमानगंज, पुलिस थाना पवई के लिए निकेत चैरसिया तहसीलदार पवई, पुलिस थाना सिमरिया के लिए प्रेमनारायण सिंह प्र. तहसीलदार सिमरिया, पुलिस थाना सुनवानीकला के लिए रतन सिंह राजस्व निरीक्षक सुनवानी, पुलिस चैकी कल्दा के लिए राज कुमार वर्मा राजस्व निरीक्षक कल्दा एवं पुलिस चैकी मोहन्द्रा के लिए रामकृपाल साकेत राजस्व निरीक्षक पवई को दायित्व सौंपा गया है।

इसी प्रकार पुलिस थाना शाहनगर के लिए संदीप सिंह प्र. तहसीलदार शाहनगर, पुलिस चैकी बोरी के लिए मंगलेश्वर सिंह राजस्व निरीक्षक शाहनगर, पुलिस चैकी हरदुआ खम्हरिया के लिए महराज सिंह राजस्व निरीक्षक हरदुआ पटेल, पुलिस थाना रैपुरा के लिए राम प्रताप सिंह प्र. तहसीलदार रैपुरा, पुलिस चोकी बीरा के लिए उमेश तिवारी प्र. नायब तहसीलदार बीरा, पुलिस थाना अजयगढ के लिए धीरज गौतम प्र. तहसीलदार अजयगढ, पुलिस चैकी खोरा के लिए शारदा प्रसाद सोनी राजस्व निरीक्षक धरमपुर, पुलिस चैकी नरदहा के लिए विनोद कुमार यादव ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, पुलिस चैकी चंदौरा के लिए लक्ष्मण सिंह राजस्व निरीक्षक मंडल बीरा, पुलिस चैकी हनुमतपुर के लिए रामनाथ प्रजापति राजस्व निरीक्षक अजयगढ तथा पुलिस चैकी पहाडीखेरा के लिए इन्द्रकुमार गौतम राजस्व निरीक्षक बृजपुर को दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि संबंधित थाने में नियम समय के पूर्व उपस्थित होकर प्रश्न पत्र निकलवाने की कार्यवाही करेंगे एवं वस्तुस्थिति से नियुक्त किए गए केन्द्राध्यक्ष एवं अपर कलेक्टर पन्ना को अवगत करेंगे।

टेड से खास

डॉ. मिरियम सिडिवी, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट

53 फीसदी स्कूलों में हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है

मैं म्यांमार में एक महिला से मिली। उनकी पहली संतान बेटी थी, वह संक्रमण के कारण तीन सप्ताह बाद ही मौत का शिकार हो गई थी। खुशकिस्मती से उस महिला की दूसरी संतान जिंदा थी। दुनिया में लाखों बच्चे अपने जन्म के एक महीने बाद ही मर जाते हैं। अगर हेल्थ वर्कर्स को हम सिर्फ एक साबुन का टुकड़ा दे दें और बच्चों को छूने से पहले वे साबुन से हाथ धो लें, तो बच्चों की मौत के इस आंकड़े को कम किया जा सकता है। इस एक बात ने मुझे इस क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों को छूने से पहले हाथ धोने और बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाने की एक आदत से दुनियाभर में लाखों बच्चों को मरने से बचाया जा सकता है। अभी भी दुनिया में हर दिन पांच साल से कम उम्र के 15 हजार बच्चे मर रहे हैं। हालांकि पिछले सालों के मुकाबले इसमें बहुत कमी आई है, लेकिन अभी भी यह आंकड़ा बहुत बड़ा है।

पांच साल से कम उम्र की बच्चों की मौत की सबसे बड़ी वजह डायरिया और निमोनिया है। बड़ी बात है कि साफ-सफाई से इन मौतों पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। बच्चों को साबुन से हाथ धुलवाने की आदत से डायरिया के मामले आधे हो सकते हैं, फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारियां एक तिहाई कम हो सकती हैं। साबुन से हाथ धोने की आदत से फ्लू, ट्राकोमा, सार्स, कोलेरा और इबोला जैसी महामारियों तक से बचा जा सकता है। 2018 में यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ के साझा अध्ययन में सामने आया था कि दुनियाभर में 53 फीसदी स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा नहीं है। स्कूल्स और सार्वजनिक जगहों पर साबुन से हाथ धोने की सुविधाएं मुहैया करवाना जरूरी है। बच्चों के साथ-साथ बड़ों में भी हाथ धोने की आदत डालना जरूरी है। आंकड़ों के अनुसार हर पांच में से चार व्यक्ति टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद अच्छी तरह से हाथ नहीं धोते। मौजूदा समय को देखते हुए हमें अपनी आदतें बदलने की जरूरत है।

(सितंबर 2014 की टेड टॉक)

हरियाणा में 1 जुलाई से स्कूल खुलेंगे, पहले 9वीं-12वीं तक के छात्र आएंगे

- एक दिन में आधे बच्चे या दो शिफ्टों में स्कूल चलाने पर विचार जारी

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

हरियाणा सरकार ने 1 जुलाई से स्कूल खोलने का फैसला किया है। अनलॉक-1 में स्कूल खोलने का फैसला लेने वाला हरियाणा पहला राज्य है। स्कूल खोलने की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी। पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं लगेंगी। दूसरे चरण में छठी से 8वीं और तीसरे में पहली से 5वीं तक की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। स्कूल खोलने को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बुधवार को अधिकारियों के साथ चर्चा की। सभी स्कूल खोलने से पहले चार-पांच स्कूल खोलकर कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों की रिहर्सल भी की जाएगी। गुर्जर ने बताया कि जिलों में शिक्षा अधिकारियों, अध्यापकों और अभिभावकों की कमेटियों से 7 जून तक सुझाव मांगे गए हैं। स्कूल खोलने में इनका भी ध्यान रखा जाएगा। स्कूलों में बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के लिए अलग-अलग प्लान तैयार किए हैं। एक दिन में 50% बच्चों को ही बुलाने की योजना बनाई गई है। दूसरी योजना यह है कि आधे-आधे बच्चों को बुलाकर स्कूल दो शिफ्टों में लगाए जाए, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। केंद्र सरकार ने अनलॉक-1 की गाइडलाइंस में स्कूल-कॉलेजों को दूसरे चरण में रखा था। इन्हें खोलने की तारीख पर जुलाई में ही फैसला लेने की बात कही गई थी।

कक्षा 11वीं, 12वीं के लिए भी नया कैलेंडर जारी

नई दिल्ली | स्कूलों के जल्द खुलने पर संशय के बीच मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए भी वैकल्पिक कैलेंडर जारी किया है। नए कैलेंडर के अनुसार विद्यार्थी घर बैठे ही योजनाबद्ध तरीके से पढ़ाई कर सकेंगे। इसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखा गया है। इससे पहले मंत्रालय ने पहली से पांचवीं, छठवीं से आठवीं और नौवीं से दसवीं कक्षा के लिए अलग-अलग वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। निशंक ने कहा कि इस कैलेंडर के माध्यम से शिक्षक अलग-अलग तकनीकों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को अभिभावकों की देखरेख में ही पढ़ा सकेंगे। कैलेंडर चार हफ्तों का है।

परीक्षा को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित

अजयगढ़। 12 वीं की परीक्षा के पूर्व की तैयारी को लेकर कलेक्टर पन्ना कर्मवीर शर्मा के आदेश के पालन में एस.डी.एम. बी.बी.पाण्डे ने उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा केंद्रों के सहायक केंद्राध्यक्षों की बैठक ली गई। बैठक में बताया गया कि अजयगढ़ अनुविभाग अन्तर्गत 8 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। जिसमें अजयगढ़ के मॉडल स्कूल परीक्षा केन्द्र के स्थान पर सरस्वती शिशु मन्दिर को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। इस केन्द्र का एस.डी.एम. श्री पाण्डे ने विगत दिनों निरीक्षण किया गया था। वहाँ पर कमरों में पंखे नहीं लगे थे साफ सफाई नहीं थी उनके द्वारा उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके पालन में बैठक में बताया गया कि उक्त स्कूल के कमरों में पंखे लगना प्रारम्भ हो गए हैं एवं साफ सफाई भी की जा रही है स बैठक में उन्होंने उपस्थित सहायक केंद्राध्यक्षों को तत्काल निरीक्षण कर सभी तैयारी पूर्ण होने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। परीक्षार्थियों को आने जाने हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु ग्रामवार समीक्षा की गई।

जारी है निजी स्कूलों की कारस्तानी ऑनलाइन के नाम पर होगी वसूली

मध्य स्वदेश ■ होशंगाबाद

जिले भर के निजी स्कूलों ने ऑन लाइन शिक्षा के नाम पर अपनी दुकान खोल ली है, साथ ही शिक्षा देना भी शुरू कर दिया है, दो एक अध्याय भी पूरे हो गए, अब बच्चों ने कितना समझा वह भगवान भरोसे है। धीरे धीरे जिसमें फीस वसूलने की घेरा बंदी शुरू है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर स्कूलों को लेकर चर्चा शुरू हो गई?

अब विडम्बना यह है, सरकार ने स्पष्ट निर्देश अभी तक जारी नही किए भ्रमित अफवाहें स्कूलों के नियम को लेकर फैलाई जा रही है। जिससे छात्रों में भ्रम की स्थिति है, कॉपी किताब खरीदने का दवाब भी बढ़ता जा रहा है, निजी स्कूल से सिलेबस निर्धारित है कौन सी किताब चलेगी निर्धारण कौन करता है क्योंकि जिन लेखकों की या प्रकाशन से मोटा मुनाफा होता है सिलेबस बनाया जाता। इसके कमीशन का हिस्सा मानो स्कूल को भी दिया जाता ? उसके भार में पालक पिस जाते है, कुछ पालक अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहते, उन्हें एंड्राइड फ़ोन लेना पड़ रहा! जरूरत और मजबूरी बने इंटरनेट कलेक्शन भी लेना पड़ रहा है, जिसमें पालकों की यह भी चिंता, इंटरनेट से आने वाली गन्दगी उनके बच्चो को खराब नहीं कर दें? जवाबदारी कौन लेगा यह जरूरी नहीं कि बच्चे स्कूल अध्ययन सामग्री ही देखे उसके सभी तरह की चीजें सामने होंगी, आज विदेशों के बच्चों की हालत हो गई वे मोबाइल के आदि हो गए उनके लिए अस्पताल बनाए जा रहे है कहीं यह स्थिति भारत की न हो जाएं ? फिर निजी स्कूल की अपनी चाल फीस वसूली है उन्होंने मेसेज भेजना शुरू कर दिए, गोपनीय मेसेज पालकों के पास पहुंचने लगे 3 महीने से बेरोजगारी की मार झेल रहा पालक हजारों रुपए फीस जमा करेगा? फीस को लेकर सरकार के निर्देश क्या है, इसके ठोस निर्देश नहीं है, क्या फीस माफ होगी या फिर बाद में देना है कुछ कहा नही जा सकता ? बरसों से चल रहे निजी स्कूल, शिक्षकों को सेलरी नही देने की कहानी बना बैठे है वे अपने शिक्षकों को तनख्वाह नहीं देंगे जबकि बरसों से निजी स्कूलों ने मोटी कमाई की है वो विपत्ति के समय अपने स्टाफ को तनख्वाह नहीं दे सकते, शोषण नीति जारी रखते हुए ये मजबूर शिक्षक को भी राजी करने में जुट गए हैं।

मूल्यांकन पूरा, अब परीक्षा की तैयारी में जुटे जिम्मेदार

दो चरणों में जांची गईं 10वीं, 12वीं की साढ़े 3 लाख उत्तरपुस्तिका

जागरण, रीवा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 10वीं, 12वीं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा हो गया। रीवा समन्वयक संस्था मार्तण्ड क्रमांक 1 ने गत 31 मई को मूल्यांकन कार्य पूरा किया। पहले व दूसरे चरण में संस्था द्वारा पांच सौ शिक्षकों से साढ़े 3 लाख उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया गया। इस कार्य में संस्था ने लगभग एक माह का समय लिया। मूल्यांकन उपरांत संस्था द्वारा डाटाशीट में माशिमं को नम्बर भेजने की कार्यवाही भी कर दी गई है।

गौरतलब है कि माशिमं ने 10वीं, 12वीं की मुख्य वार्षिक परीक्षा का आयोजन विगत 1 मार्च से प्रारम्भ कराया था। दोनों विषयों के अधिकांश विषयों की परीक्षा हो चुकी थी। इस दरम्यान गत 22 मार्च से जनता कर्फ्यू और फिर लॉकडाउन हो गया, जिसके चलते समस्त परीक्षाएं स्थगित हो गई। यहीं नहीं, प्रायः 18 मार्च से शुरू होने वाला मूल्यांकन कार्य भी स्थगित हो गया। जैसे-तैसे माशिमं ने गत 1 मई से दोनों कक्षाओं की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू कराया, जो अब जाकर पूरा हो गया है।

9 जून से शेष विषयों की परीक्षा : अब समन्वयक संस्था आगामी 9 जून से होने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट गया है। माशिमं के निर्देशानुसार 9 से 16 जून के बीच दो पाली में 12वीं के शेष विषयों की परीक्षा होनी है, जिसके लिए पेपर वितरण के अलावा अन्य कार्यवाही हो चुकी है। मुख्य रूप से अब सोशल डिस्टेंसिंग समेत स्वास्थ्य, सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस दिशा में ठोस कार्यवाही करने के निर्देश भी शासन-प्रशासन ने दिए हैं। चूंकि परीक्षा व मूल्यांकन में विलम्ब हुआ है। इस लिहाज से परीक्षा परिणाम जारी होने में भी इस दफा विलम्ब होगा। सम्भावना जताई जा रही है कि जुलाई माह के पहले सप्ताह में माशिमं द्वारा परिणाम घोषित किए जा सकते हैं।

बोर्ड परीक्षा के तैयारियों की समीक्षा बैठक आज

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकण्डरी वार्षिक परीक्षा के शेष प्रश्नपत्रों की परीक्षा 9 जून से आरंभ हो रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक 4 जून को दोपहर 2 बजे से आयोजित की जा रही है। कलेक्टर बसंत कुर्रे बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों तथा बोर्ड परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

डिजीलेप से पढ़ाई कर रहे बच्चों से मिलने उनके घर पहुंचे कमिश्नर

कहा-डिजीलेप से लॉकडाउन में भी घर-घर जल रही शिक्षा की ज्योति

जागरण, रीवा

कोरोना संक्रमण के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद है। ऐसी परिस्थिति में भी विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई की सुविधा देने के लिये मध्यप्रदेश शासन ने डिजिटल लर्निंग इनहैंसमेंट प्रोग्राम डिजीलेप शुरू किया है। इसमें मोबाइल एप तथा टेलीविजन एवं रेडियो के माध्यम से कक्षा एक से 12वीं तक के विद्यार्थियों को पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है। डिजीलेप से लॉकडाउन में भी घर-घर शिक्षा की ज्योति जल रही है। रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ अशोक कुमार भार्गव ने ग्राम खैरी हरिजन बस्ती तथा ग्राम दोही में बच्चों के घर जाकर उनसे शैक्षणिक गतिविधि की जानकारी ली।

कमिश्नर डॉ भार्गव ने हरिजन बस्ती खैरी में शालू साकेत, कविता, रानी साकेत आदि बच्चों से डिजीलेप से मिल रही शैक्षणिक सामग्री की जानकारी ली। उन्होंने बच्चों के अभिभावकों से भी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देने का अनुरोध किया। कमिश्नर ने कहाकि सभी माता-पिता बच्चों को टेलीविजन तथा मोबाइल से दी जा रही शैक्षणिक सामग्री का अवलोकन करें। बच्चों द्वारा किये गये होमवर्क का भी अवलोकन करें। इसके बाद कमिश्नर

डॉ भार्गव पूर्व माध्यमिक शाला दोही में बच्चों से डिजीलेप के संबंध में चर्चा की। मोबाइल एप से पढ़ाई कर रही सोनिया साकेत, रीना, अंजू, राजू, सरिता साकेत, ज्योति तथा अन्य बच्चों ने बताया कि मोबाइल से प्रतिदिन होमवर्क मिलता है। एक ही मोबाइल से कई बच्चे बारी-बारी से पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों ने कमिश्नर डॉ भार्गव को कोरोना से बचाव के संबंध में बनाये गये सुंदर चित्र दिखाये। कमिश्नर ने बच्चों की शिक्षा की लगन की प्रशंसा की।

कठिन परिस्थिति तथा कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन में भी आधुनिक सूचना संचार तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा का अवसर घर बैठे मिल रहा है। कमिश्नर ने डिजीलेप के क्रियान्वयन की प्रशंसा की। कमिश्नर ने बच्चों तथा ग्रामवासियों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क के उपयोग, फिजिकल दूरी बनाये रखने, नियमित अंतराल के बाद साबुन से हाथ धोने तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों की समझाइश दी। इस अवसर पर संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अंजनी कुमार त्रिपाठी, डीपीसी सुदामा गुप्ता, वीआरसी प्रवीण शुक्ला, शिक्षकगण तथा ग्रामवासी उपस्थित रहे।

ग्रामवासियों ने की मीठे पानी की मांग

भ्रमण के समय दोही में ग्राम वासियों ने नाले की सफाई, मीठा पेयजल तथा बिजली का पोल लगाने के संबंध में अनुरोध किया। कमिश्नर डॉ भार्गव ने नगर निगम के अधिकारियों को इस संबंध में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये।

कमेटी को एक हजार कॉलेजों की फीस तय करने अध्यक्ष का इंतजार

- बचे हुए कॉलेजों से 6 जून तक बुलाए हैं ऑनलाइन आवेदन
- ऑनलाइन होगी आवेदनों की स्क्रूटनी

नगर संवाददाता, भोपाल

प्रदेश के 1 हजार से ज्यादा इंजीनियरिंग, मेडिकल, बीएड, डीएड सहित अन्य शिक्षण संस्थानों की फीस तय करने प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति को अध्यक्ष का इंतजार है। कमेटी के अध्यक्ष कमलाकर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद से सरकार यहां नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। जबकि अध्यक्ष का इस्तीफा 15 दिन पहले ही सरकार के पास पहुंच चुका है। इधर, कमेटी अधिकारियों ने जल्द से जल्द फीस तय करने की प्रक्रिया पूरी करने बचे हुए कॉलेजों से दोबारा ऑनलाइन आवेदन बुलाए हैं। लॉकडाउन से पहले कमेटी के पास करीब 600 कॉलेजों के ही आवेदन आए थे। इससे आधे से ज्यादा कॉलेज आवेदन करने से वंचित रह गए थे। इसको देखते हुए कमेटी ने दोबारा ऑनलाइन आवेदन बुलाए हैं। सभी निजी कॉलेज 6 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद कॉलेजों के लिए फीस तय की जाएगी। हालांकि इस बार प्रदेश के 90 फीसदी इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य शिक्षण संस्थानों की फीस में बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि कॉलेज खुद फीस नहीं बढ़वाना चाहते हैं। फीस कमेटी के पास अब तक आए आवेदनों में ज्यादातर ने अपनी जस की तस फीस रखे जाने का प्रस्ताव कमेटी को दिया है। पिछले साल फीस बढ़ाए जाने की मांग कर रहे बीएड, डीएड कॉलेज भी इस बार फीस बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं है। इससे इनकी फीस में भी बढ़ोत्तरी नहीं होगी। इंजीनियरिंग के सिर्फ उन कॉलेजों की फीस बढ़ेगी, जिनकी ज्यादा डिमांड होती है। इनकी फीस में भी 5 से 10 फीसदी की ही बढ़ोत्तरी होगी। हालांकि निजी मेडिकल कॉलेज फीस बढ़वाना चाहते हैं, लेकिन उनकी फीस में भी अब अगले शिक्षण सत्र में ही बढ़ोत्तरी हो पाएगी।

ऑनलाइन देखे जाएंगे कॉलेजों के आय-व्यय

फीस तय किए जाने के लिए इस बार आवेदनों की स्क्रूटनी पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन ही कॉलेजों के आय-व्यय को देखा जाएगा। इसी के मुताबिक उनकी फीस तय होगी।

फीस तय करने में हो चुकी है तीन महीने की देरी

प्रवेश और फीस विनियामक कमेटी में अध्यक्ष नहीं होने से प्राइवेट कॉलेजों में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों की फीस तय नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन की वजह से कमेटी का ऑफिस नहीं खुलने से फीस तय नहीं हो सकी थी। इसके बाद सरकार के दबाव में कमलाकर सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पूरी कमेटी ही भंग हो गई। फीस तय होने की प्रक्रिया में करीब तीन महीने की देरी हो चुकी है।

ऑनलाइन करना होगा आवेदन, विवि आने की जरूरत नहीं

छात्रों की समस्याओं का घर बैठे होगा निदान, विवि ने जारी किए नंबर

ग्वालियर,न.सं.

कोरोना काल के बीच जीवाजी विश्वविद्यालय की गतिविधियां शुरू हो गई हैं और पचास प्रतिशत कर्मचारी विवि में आकर काम निपटा रहे हैं। बाहरी लोगों व छात्रों का प्रवेश अभी तक पूरी तरह प्रतिबंधित है।

उसके बाद भी कुछ छात्र अपनी समस्याएं लेकर पहुंच रहे हैं या फिर अधिकारियों के पास उनके फोन आ रहे हैं। इसे देखते हुए विवि प्रशासन ने छात्रों की समस्याओं को घर बैठे ही निपटाने की योजना बनाई है। इसके लिए विवि ने छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन मंगाए हैं। साथ ही अधिकारियों के मोबाइन नंबर भी जारी किए हैं, जिन पर छात्र अपनी समस्याएं भेज सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन भी आवेदन किए जा सकेंगे।

करीब ढाई माह से बंद विवि की गतिविधियां एक सप्ताह पहले शुरू हो गई हैं। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कर्मचारियों को बुलाया जा रहा है और वह जरूरी काम ही निपटा रहे हैं। अभी विवि आधा दिन ही खुल रहा है और इस दौरान परीक्षा व गोपनीय संबंधी काम पहली प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। चूंकि परीक्षाओं के आवेदन भरने की तिथि तय कर दी गई हैं, इसलिए वह छात्र सबसे अधिक परेशान है जिनके परिणाम रुके हैं या फिर जिनकी अंकसूची में करेक्शन है। इसलिए विवि प्रशासन ने तय किया है कि छात्रों की समस्याओं का ऑनलाइन ही निराकरण किया जाएगा। छात्र सहायक कुलसचिवों के मोबाइल नंबर 79875-89479, 95899-92748 आवेदन भेज सकते हैं। इसके अलावा विवि की वेबसाइट के होम पेज पर हेल्म मेल पर भी अपनी समस्यां प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन आने के बाद छात्रों की समस्याओं का ऑनलाइन ही निराकरण किया जाएगा, ताकि वह परीक्षा आवेदन भर सकें।

विवि में लगातार होंगे चार वेबिनार

विवि में इन सात दिनों में लगातार चार वेबिनार होंगे। ये चार जून से शुरू होकर 8 जून तक चलेंगे। ये सभी वेबिनार में अलग-अलग विषयों पर होंगे। इनमें चार जून को सुबह 11 बजे से सोशल वर्क एजुकेशन- न्यू चैलेंजेज एंड वर्केबल चेंजेज पर होगा। पांच जून को कैमिस्ट्री विभाग की ओर से वेस्ट मैनेजमेंट इयूरिंग द कोविद-19 पेंडेमिक विषय पर होगा। जबकि छह जून को लाइब्रेरी साइंस विभाग की ओर से वेबिनार आयोजित किया जाएगा। सात जून को दो दिवसीय वेबिनार टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से होगा।

इनका कहना है

छात्रों की समस्याओं का घर बैठे निराकरण होगा। अधिकारियों के वाट्सएप नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर छात्र आवेदन भेज सकते हैं। मेल पर भी समस्या से अवगत कराया जा सकता है। गंभीरता के साथ ही छात्रों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा।

प्रो. आनंद मिश्रा
कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय

निजी विद्यालय संचालक नहीं दे रहे शिक्षकों को वेतन

अभिभावकों से ले रहे हैं फीस, अधिकतर स्कूलों के संचालकों के खिलाफ मिल रही शिकायतें

स्टार समाचार | सीधी

कोरोना की वजह से लाकडाउन के कारण स्कूलें बंद होने की वजह से अधिकतर स्कूल संचालक भले ही शिक्षकों को तीन माह का वेतन न देने का निर्णय लिये हैं लेकिन अभिभावकों से छात्रों के फीस की वसूली कर रहे हैं। इस मामले को लेकर स्थानी तौर पर स्कूल प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है।छात्रों से छुट्टी के दौरान फीस तो लिया जा रहा है लेकिन निजी स्कूल के संचालक शिक्षकों का वेतन नहीं दे रहे हैं। इस पर जांच की जाये तो कई विद्यालय के संचालक कठघरे में आ सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 13 मार्च के बाद स्कूलों की छुट्टी करने का फरमान प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। इस दौरान कई निजी स्कूल के संचालकों ने आधी-अधूरी परीक्षाएं ली थीं इसके बाद अवकाश की घोषणा होने के बाद विद्यालय बंद कर दिया गया जो कि अब निरंतर विद्यालय बंद हैं। इन सबके बावजूद भी विद्यालय प्रबंधक द्वारा नियमों को दरकिनार कर अभिभावकों से फीस लेने के लिए बाध्य किया जा रहा है। देखा जावे तो शासन ने भी जो दिशा-निर्देश दिया है उसके तहत ट्यूशन फीस तीन महीने लेने के लिए आदेश दिया है। इस आदेश में अभिभावकों पर सरकार द्वारा कोई रहम नहीं बरती गई है। ट्यूशन फीस का मतलब कोई रियायत नहीं मानी जा सकती है। विद्यालय प्रबंधकों द्वारा पहले ही किस्त के अनुसार राशि तय कर के अभिभावकों से फीस की वसूली की जाती रही है। ऐसे में ट्यूशन फीस लेने का जो हथकंडा शासन द्वारा दिया गया है उसका कोई मायने समझ में नहीं आ रहा है। इसी का फायदा उठाते हुए निजी विद्यालय के संचालकों द्वारा फीस में कोई रियायत न देने का निर्णय लिया है। भले ही 15 मार्च से लेकर अब तक विद्यालय संचालित नहीं हैं लेकिन छात्रों से फीस यथावत ली जा रही है। जबकि अधिकतर निजी विद्यालय के संचालकों ने लाकडाउन का बहाना कर शिक्षकों को वेतन देने से मना कर दिये हैं। हालांकि कुछ विद्यालय पहले भी गर्मी के दौरान दो माह का वेतन नहीं देते थे लेकिन इस बार तीन माह का वेतन न देने को लेकर भी प्रायवेट विद्यालय में अध्ययापन कार्य कर रहे शिक्षको में नाराजगी कम नहीं है। पड़ताल के बाद शिक्षकों ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि यदि हम संबंधित विद्यालय में पढ़ाते हैं तो विरोध करने के बाद हमें आगामी सत्र में हटा दिया जाएगा। जिस वजह से शिक्षकों ने नाम न बताते हुए इतना ही कहा कि निजी विद्यालय के संचालक जब छात्रों से पूरे तीन महीने का शुल्क वसूल रहे हैं तो शिक्षकों को भी वेतन देना चाहिए। कोरोना को लेकर लाकडाउन के कारण शिक्षकों की भी माली हालत खराब है। प्रायवेट विद्यालय में शिक्षक कितना वेतन पाते हैं यह सबको मालुम है, इसके बावजूद भी उनके साथ अधिकतर विद्यालय के संचालकों द्वारा नाइंसाफी की जा रही है।

अभिभावको में भी है नाराजगी

लाकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों ने कहा कि तीन महीने की फीस सरकार को माफ कर देना चाहिए परन्तु शासन ने जो फरमान जारी किया है उससे अभिभावकों की जेब खाली हो रही है। प्रायवेट विद्यालय में वैसे भी भारी-भरकम फीस ली जाती है। यदि तीन महीने की फीस माफ हो जाती तो कुछ हद तक राहत मिल सकती थी। लेकिन सरकार द्वारा स्पष्ट आदेश जारी न करने की वजह से निजी स्कूल के संचालक फीस माफी के लिए तैयार नहीं हैं। अभिभवकों का कहना है कि सहानुभूति बतौर कलेक्टर एवं स्कूल संचालक कम से कम तीन महीने का फीस तो माफ करा दें जिससे की आर्थिक तंगी का सामना कर रहे अभिभाकों को समस्या न होने पावे।

टीचर्स को नौकरी से निकालने के मामले में तीन स्कूलों को नोटिस

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर। जिला शिक्षा अधिकारी ने टीचर्स को नौकरी से निकालने और आधा वेतन देने के मामले में तीन स्कूलों को नोटिस जारी किया है। स्कूलों से तीन दिन में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। उल्लेखनीय है कि एक टीचर ने बिना नाम के शिकायत दी है कि स्मॉल वंडर स्कूल बल्देवबाग से 70 टीचर्स को नौकरी से निकाल दिया गया है। उन्हें अप्रैल माह में आधा वेतन दिया गया। इसके साथ ही आदित्य कॉन्वेन्ट स्कूल और ज्ञान गंगा स्कूल से भी टीचर्स को नौकरी से निकाला गया है। जिला शिक्षा अधिकारी सुनील नेमा ने बताया कि इस मामले में यदि नौकरी से निकाले गए टीचर्स अलग-अलग शिकायत करेंगे तो उन्हें कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस संबंध में प्रशासन ने पहले ही सख्त निर्देश दे रखें हैं कि बच्चों से फीस वसूलने के बाद भी स्कूल शिक्षकों को वेतन न देने या नौकरी से निकालने का काम करते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।

डीईओ ने तीन दिन में माँगा प्रतिवेदन

परीक्षार्थी बगैर किसी डर के परीक्षा की तैयारी करें

स्टार समाचार | पन्ना

आगामी 9 से 16 जून तक हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थी मन लगाकर परीक्षाओं की तैयारी करें। मन में किसी भी तरह की शंका अथवा डर महसूस न करें। प्रत्येक परीक्षार्थी का जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सहयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परीक्षा केन्द्र पर 01 घण्टे पहले पहुंच जाएं। परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व सभी की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। यह एक साधारण जांच है सभी विद्यार्थी अनिवार्य रूप से कराएं। सभी विद्यार्थी डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनिट पूर्व उत्तर पुस्तिका एवं 05 मिनिट पूर्व प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। प्राप्त प्रश्न पत्रों का ध्यानपूर्वक हल करें। हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट एवं हायर सेकेण्डरी व्यवसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी। सामान्य विद्यार्थी के लिए प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दृष्टिहीन मूकबधिर दिव्यांग नियमित विद्यार्थियों की परीक्षाएं दोपहर 02 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। प्रथम पाली में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रातः 8 बजे तक तथा दूसरी पाली के विद्यार्थियों को दोपहर 01 बजे तक परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा। परीक्षा केन्द्र में सुबह 8.45 बजे एवं दोपहर 01.45 बजे के बाद किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नही दिया जाएगा। सभी विद्यार्थी समय पर आए। सभी विद्यार्थी कोरोना वायरस संक्रमण रोकने संबंधी नियमों के तहत मुंह, नाक पर मास्क या कपड़ा बांधने के साथ हाथों को सेनेटाइज करते रहें।

फीस वसूली के लिए उतारू प्राइवेट संस्थान

रीवा(नव स्वदेश)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता विवेक पांडेय ने कहा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित समस्त महाविद्यालय तथा विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर बेवजह फीस के लिए अभी से दबाव बनाया जा रहा है जबकि इस वैश्विक महामारी कोरोना के कारण देश भर में लागू लॉक डाउन के कारण छात्रों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। लेकिन जैसे ही शासन द्वारा यह आदेश दिया गया कि फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा विश्विद्यालयों द्वारा संचालित कराई जाए वैसे ही समस्त शैक्षणिक संस्थानों द्वारा छात्रों के ऊपर दवाब बनाना शुरू कर दिया गया जबकि शासन द्वारा यह आदेश है कि स्थिति सामान्य होने तक महाविद्यालय छात्रों के ऊपर अनावश्यक रूप से फीस के लिए दवाब न बनाये। रीवा जिले के संस्थानों ने अपने आप को शासन के आदेश के ऊपर समझना शुरू कर दिया है।

लॉकडाउन में निजी विद्यालयों ने अभिभावकों पर बढ़ाया आर्थिक बोझ

सारे नियम-कायदों को खारिज कर सिर्फ लूटने की जिद, शासन पहले से ही नतमस्तक

जागरण, रीवा। पिछले 3 माह से रहे लॉकडाउन ने लोगों की जिंदगी में आर्थिक समस्या उत्पन्न की है। अब निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों पर आर्थिक बोझ फिर से बढ़ गया है। राज्य शासन ने ट्यूशन फीस वसूलने की छूट देकर निजी विद्यालयों की जैसे हौसला अफजाई कर दी है। यही वजह हो सकती है कि अब निजी विद्यालयों से साठगांठ कर निजी प्रकाशकों ने पुस्तकें महंगी कर दी हैं। निजी विद्यालयों ने नर्सरी कक्षा की जिन किताबों का सेट खरीदने के लिए अभिभावकों को कहा है, वह इस बार 2 हजार रूपये में आ रही हैं। जबकि इन किताबों की कीमत पिछले सत्र में 17सौ से 18सौ रूपये रही। यहीं नहीं, दुकानदारों द्वारा पुस्तकों के साथ कॉपी, पेंसिल, रबड़, रोल कलर सेट जैसी सामग्री भी खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश किया जा रहा है। जबकि जिला कलेक्टर ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किये हैं कि किसी भी अभिभावक को जबरन पाठ्य सामग्री खरीदने को विवश नहीं किया जा सकता। फिर भी निजी विद्यालयों व कुछ चुनिंदा पुस्तक विक्रेताओं की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग के अधिकारी भी राज्य सरकार की तरह निजी विद्यालयों के आगे नतमस्तक हो चुके हैं।

नहीं मान रहे कलेक्टर के आदेश: गौरतलब है कि शासन ने सरकारी किताबों को चलाने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश को भी धता बताते हुए निजी प्रकाशकों की किताबों को ही खरीदने के लिए अभिभावकों को विवश किया जा रहा है। चूंकि इनमें निजी विद्यालयों को सीधा कमीशन मिलता है इसलिए इस लॉकडाउन में भी अभिभावकों को निचोड़ने में कोई कसर निजी विद्यालय नहीं छोड़ रहे। निजी विद्यालयों ने किताबों के सेट की सूची अभिभावकों को दी है। इसमें नर्सरी के अलावा कक्षा 5वीं तक की किताबों को 3 हजार रूपये तक लोगों को खरीदना पड़ रहा है।

ड्रेस, जूता, मोजा में भी कमीशन

इसके अतिरिक्त ड्रेस, जूता, मोजा, टाई आदि के लिए भी हमेशा की तरह निजी विद्यालयों के साथ दुकानदारों का समझौता है। इस समझौते के तहत ही निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित दुकान से ही अभिभावकों को ड्रेस आदि खरीदना पड़ रहा है। इस खुली लूट पर नियंत्रण कसने के लिए फिलहाल शासन-प्रशासन के जिम्मेदारों के पास कोई उपाय नहीं है।

क्या कहते है अभिभावक

प्राइवेट स्कूल वाले अभी भी शासन के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। हर साल की तरह इस बार भी किताबें बदल दी गई हैं। इस वर्ष भी किताबों की संख्या बढ़ाकर बैग का वजन बढ़ा दिया गया है। साथ ही पुरानी किताबें घर के दूसरे बच्चों के काम की नहीं बची।

उपेंद्रचंद्र दुबे, निवासी उपरहटी

प्राइवेट स्कूल की हर बात अभिभावकों को माननी पड़ती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए नाजायज मांगों को भी स्वीकार करना पड़ता है। उस पर भी दुकानदारों की धौंस झेलन पड़ रही है। किताबें इस बार भी महंगी हो गई हैं। लॉकडाउन में आमदनी वैसे भी न के बराबर थी। अब पढ़ाई के सामान भी महंगे कर दिए गए हैं।

संजय मिश्रा, निवासी बोदाबाग

बोर्ड परीक्षा के तैयारियों की समीक्षा बैठक आज

रीवा । माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित हायर सेकण्डरी वार्षिक परीक्षा के शेष प्रश्नपत्रों की परीक्षा 9 जून से आरंभ हो रही है। बोर्ड परीक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक 4 जून को दोपहर 2 बजे से आयोजित की जा रही है। कलेक्टर बसंत कुर्रे बैठक में परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों तथा बोर्ड परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये हैं।

कन्या उमावि जहांगीराबाद की जगह नूतन सुभाष टीटी नगर होगा केंद्र

कंटेनमेंट एरिया के केंद्रों में से एक बदला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

राजधानी के अलग-अलग कंटेनमेंट एरिया में आने वाले कक्षा 12वीं के परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर आखिर एक सप्ताह बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने फैसला ले लिया है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने चिन्हित किए गए 19 परीक्षा केंद्रों में से शासकीय कन्या उमावि जहांगीराबाद में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा केंद्र की जगह स्टूडेंट्स को टीटी नगर स्थित शासकीय उमावि नूतन सुभाष में परीक्षा देनी होगी।

इन स्कूलों के स्टूडेंट्स होंगे प्रभावित

जहांगीराबाद स्थित परीक्षा केंद्र शास. कन्या उमावि में शा. उमावि महाराणा प्रताप जहांगीराबाद के 80, अशा.एम के गांधी उमावि जहांगीराबाद के 18, अशा.बोरबन उमावि जहांगीराबाद के 44, अशा. ग्लोरियस उमावि जहांगीराबाद के 28, अशा. ब्रिलियंट कान्वेंट उमावि बरखेड़ी के 119 मिलाकर कुल 289 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल होते थे। अब इन संस्थानों के स्टूडेंट्स को शेष विषयों की परीक्षा के लिए नए परीक्षा केंद्र शास उमावि नूतन सुभाष टीटीनगर में जाना होगा।

कंटेनमेंट एरिया के कारण बोर्ड परीक्षा के चार केन्द्रों में स्थान परिवर्तन

रीवा । कोरोना संक्रमण के कारण जिले की कुछ बस्तियों को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है जिसके कारण यहां आवागमन प्रतिबंधित है। कंटेनमेंट क्षेत्र में होने के कारण 9 जून से आरंभ हो रही बोर्ड परीक्षा के चार परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में अपर कलेक्टर श्रीमती इला तिवारी ने बताया कि तहसील हुजूर के ग्राम गोड़हर के परीक्षा केन्द्र को उमादत्त विद्यालय बनकुइयां रोड ढेकहा में बनाया गया है। रीवा नगर के ज्ञानोदय विद्यालय परीक्षा केन्द्र को सेन्ट्रल एकेडमी विद्यालय में बनाया गया है। त्योंथर तहसील के ग्राम कटरा के परीक्षा केन्द्र को अब ग्राम जमुई के स्कूल में बनाया गया है। तहसील गुढ़ के ग्राम खझुहा के परीक्षा केन्द्र को ग्राम लक्ष्मणपुर में बनाया गया है। सभी संबंधित एसडीएम, बीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा बीआरसी नवीन स्थल पर बनाये गये परीक्षा केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करें। सभी परीक्षार्थियों को भी इस संबंध में सूचना उपलब्ध करायें।

थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मिलेगा प्रवेश

दूसरे जिलों के 269 छात्र रीवा में देंगें हायर सेकेण्डरी की बोर्ड परीक्षा

नगर संवाददाता। रीवा

लॉकडाउन की वजह से प्रभावित बोर्ड परीक्षा के शेष पेपर की तैयारी तेज है। हाई स्कूल के तो अब शेष पेपर नहीं होंगे, लेकिन हायर सेकण्डरी के बाकी पेपर नौ जून से कराए जाएंगे। तमाम छात्र इस बीच दूसरे जिलों में फंसे है। इसलिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि जिस जिले में छात्र मौजूद है, वहीं परीक्षा देंगे। रीवा जिले में दूसरे जिलों के ऐसे 269 छात्र है, जिन्हें हायर सेकण्डरी के शेष पेपर में शामिल होगा। इस तरह ये छात्र अब रीवा जिले के ही केन्द्रों में परीक्षा देंगे। वहीं रीवा जिले के जो छात्र दूसरे जिलों में फंसे हैं, उनकी संख्या अभी फाइनल नहीं हो पाई है।

प्रवेश पत्र ही होगा पास

ऐसे छात्र जो कंटेनमेंट क्षेत्र में होंगे, उनके लिए यह निर्देश दिया गया है कि उन्हें परीक्षा में शामिल कराया जाए। यदि छात्र के घर में कोई कोरोना का मरीज नहीं है तो उसे परीक्षा देने के लिए कंटेनमेन्ट जोन से निकलने दिया जाए। इसकी व्यवस्था एसपी द्वारा की जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा गया कि प्रवेश पत्र को ही पास माना जाएगा।

थानों में वेरीफिकेशन आज

बोर्ड परीक्षा के शेष विषयों के जो पेपर थानों में रखे हैं, उनका वेरीफिकेशन करने के निर्देश दिए गए है। केन्द्राध्यक्षों से कहा गया है कि गुरुवार की शाम तक थानों में जाकर यह सुनिश्चित कर लें कि पेपर सुरक्षित हैं। इसकी रिपोर्ट निरीक्षण कर तत्काल भेजने को कहा गया है, ताकि पेपर की कहीं भी परीक्षा के लिए कमी न होने पाएं।

डिस्पोजल गिलास में मिलेगा पानी

कोरोना को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों को सेनिटाइज कराया जाएगा। यह भी निर्देश दिया गया है कि केन्द्र में परीक्षार्थियों को पानी देने के लिए डिस्पोजल गिलास की व्यवस्था की जाए। वैसे यह भी कहा गया है कि यदि परीक्षार्थी अपने घर से ही पानी लाएं तो बेहतर रहेगा।

हर केन्द्र में मौजूद होंगे स्वास्थ्यकर्मी

प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में एक-एक स्वास्थ्यकर्मी आवश्यक रुप से मौजूद रहेंगे। केन्द्राध्यक्षों को मॉस्क, साबुन, सेनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी करनी होगी। कोरोना को लेकर केन्द्रों में पूरी सावधानी रखी जाएगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग में कहा गया है कि आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर कर ली जाएं। पेपर के लिए केन्द्राध्यक्षों की बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह बैठक 4 जून को होगी।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए निर्देश

बुधवार को स्कूल शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों ने भोपाल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए नौ जून से होने वाली परीक्षाओं को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि प्रत्येक परीक्षार्थी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। इतना ही नहीं मॉस्क लगाना अनिवार्य होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग में जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण अंजनी त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल, माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय अधिकारी दाहिमा, रमसा प्रभारी डॉ. पीएल मिश्रा, शासकी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक-एक के प्राचार्य जीप उपाध्याय, मूल्यांकन अधिकारी एसपी सोनी आदि मौजूद रहे।

आरजीपीवी अंतिम वर्ष की परीक्षा दो बार में आयोजित होगी

भोपाल। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं दो बार में आयोजित कराने की तैयारी चल रही है। पहली बारी में 23 से 29 जून तक परीक्षा होंगी। जिसके लिए छात्रों से ही पूछा जा रहा है कि वे परीक्षा दे सकेंगे या नहीं। जो छात्र इस बार परीक्षा में शामिल नहीं होंगे वह अगली बार परीक्षा दे सकेंगे। परीक्षा को लेकर मुश्किल मध्य प्रदेश से बाहर के छात्रों के लिए है, जिन्हें परीक्षा देने के लिए मध्य प्रदेश आना होगा। ऐसी स्थिति में आरजीपीवी ने परीक्षा के लिए छात्रों को विकल्प दिया है कि वे अभी आयोजित होने जा रही परीक्षा देना चाहते हैं या नहीं। हालांकि परीक्षा नहीं देने का विकल्प चुनने पर छात्रों को कारण भी विश्वविद्यालय को बताना होगा।

नहीं जाना होगा अन्य जिले

कारण से संतुष्ट होने पर आरजीपीवी इन छात्रों की परीक्षा जुलाई या अगस्त में आयोजित करेगा। इसके साथ ही आरजीपीवी ने तय किया है कि प्रदेश में जो छात्र जहां रह रहा है, उसे उसी जिले में आरजीपीवी से संबद्ध कॉलेज को परीक्षा केन्द्र के तौर पर आवंटित कर दिया जाएगा। इससे छात्र को परीक्षा देने के लिए अन्य जिलों में नहीं जाना होगा। हालांकि प्रदेश के बाहर के छात्रों को प्रदेश में आकर ही परीक्षा देनी होगी। दरअसल, आरजीपीवी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा इसी महीने आयोजित कराने जा रहा है। परीक्षा फॉर्म जमा करने का सिलसिला सोमवार से दोबारा शुरू हुआ है। जिन छात्रों ने पहले फॉर्म भर दिया था, उन्हें भी अपने फॉर्म में उक्त जानकारी अपडेट करनी होगी। इसी आधार पर आरजीपीवी परीक्षा आयोजित करेगा।

इनका कहना है

अनलॉक 1 के तहत 1 जून से देश में यातायात व्यवस्था में ढील दी गई है। यदि प्रदेश के बाहर का कोई विद्यार्थी चाहता है तो इस बार होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकता है। विवि ने तो यह च्वाइस विद्यार्थी के हितों को देखते हुए ही रखी है कि वे यदि अभी संभव नहीं है तो अगले बार में परीक्षा दे सकते हैं। अगली बार होने वाली परीक्षा की तारीख जल्द घोषित कर दी जाएगी। विवि का प्रयास बच्चों की हर संभव मदद करने का है। यदि किसी छात्र को पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स हैं तो वो अपनी संस्था से संपर्क कर डाउट्स क्लीअर कर सकता है।

प्रो. सुनील कुमार, कुलपति, आरजीपीवी